[2020] 11 एस. सी. आर 170

गोपाल प्रसाद

बनाम्

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और अन्य

(दीवानी अपील सं. 8225/2012)

28 मई, 2020

[इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी, न्यायमूर्तिगण]

बिहार सेवा संहिता, 1952 -विनियम. 73-बिहार पेंशन नियम, 1950-सेवानिवृत्ति-अपीलार्थी बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के कर्मचारी थे-सेवा में प्रवेश के समय उनकी आयु 15 वर्ष, 6 महीने थी-उस समय सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी जो कि 30.03.2005 को बोर्ड की बैठक द्वारा 60 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी-पेंशन नियम, 1950 के तहत, पेंशन के लिए योग्यता सेवा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है-बिहार सेवा संहिता, 1952 के तहत सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। समिति ने 15.01.2004 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में प्रवेश किया है, अपनी नियुक्ति की तारीख को अपनी आयु 18 वर्ष मानते हुए, उन्हें श्रेणी 4 के मामले में 60 वर्ष और श्रेणी 3 के मामले में 58 वर्ष पूरे होने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा-इसके संकल्प दिनांक 15.01.2004 को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसने 42 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी कर ली है जिसे एक कर्मचारी प्रदान कर सकता है और वह 42 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है-क्या किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले केवल इसलिए सेवानिवृत्त किया जा सकता है क्योंकि उसने योग्यता सेवा के 42 वर्ष पूरे कर लिए हैं-अभिनिर्धारितअजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति के अनुसार-नियमों की योजना से यह स्पष्ट है

कि बिहार सेवा संहिता 1952 के विनियम 73 के तहत निधारित सेवानिवृति आयु सेवानिवृति उद्येश्य के लिए लागू होगी और पेंशन नियम, 1950 को ध्यान में रखते हुए किसीर व्यक्ति को 42 वर्ष की सेवा पूरी करने की आयु से अधिक जारी नहीं रखा जा सकता है । यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि सरकारी कर्मचारी जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 42 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, दोनों अंतर्निहित हैं, उन्हें नियमों की योजना के संदर्भ में सेवानिवृत्त होना पड़ता है-इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति द्वारा.-एक व्यक्ति को केवल सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु प्राप्त करने पर ही सेवानिवृत्त किया जा सकता है जब तक कि नियम स्पष्ट रूप से सेवा की अवधि को सेवानिवृत्ति का मानदंड नहीं बनाते हैं -बिहार सेवा संहिता का विनियम. 73 किसी भी सेवानिवृति अवधि का निर्धारण नहीं करता है-सेवानिवृत्ति के मानदंड के रूप में -सेवा अभिलेख में दर्ज अपनी जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपीलार्थी को सेवानिवृत्त करने का निर्णय इस प्रकार कायम नहीं रखा जा सकता है-राय के अंतर को देखते हुए बड़ी पीठ को संदर्भित मामला-सेवा कानून-अनुबंध अधिनियम, 1872 -धारा 11-व्यस्कता अधिनियम, 1875 -धारा. 3.ए.

राय के मतभेद को देखते हुए मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित

अजय रस्तोगी न्यायमूर्ती, के अनुसार

1. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तें आम तौर पर वैधानिक नियमों द्वारा या इसकी अनुपस्थिति में, नियमों या प्रशासनिक निर्णयों के तहत एक बाध्यकारी बल के साथ शासित होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति केवल वयस्कता की आयु प्राप्त करता है वह सेवा के वैध अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 में यह परिभाषित किया गया है कि कौन अनुबंध करने के लिए सक्षम है और यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि सेवा के वैध अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, किसी को बहुसंख्यक अधिनियम, 1875 के

संदर्भ में वयस्कता की आयु प्राप्त करनी होगी और बहुमत अधिनियम, 1875 की धारा 3 के तहत वयस्कता की आयु क्या हो सकती है, इसे परिभाषित किया गया है। [पैरा 13,14] [181-सी, ई]

2. निर्विवाद रूप से, तत्काल मामले में अपीलार्थी मई 1970 में सेवा में प्रवेश की तारीख को नाबालिग था और जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट नियम न हो, नाबालिग सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए पात्र/योग्य नहीं है। यह सच है कि प्रवेश स्तर पर न्यूनतम आयु हमेशा नियम बनानेवाले प्रधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। तत्काल मामले में, राज्य प्राधिकरण अपने पेंशन नियम, 1950 के तहत सरकारी कर्मचारी की योग्यता सेवा निर्धारित करता है जिसे 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी किए गए संशोधन द्वारा बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यदि बिहार सेवा कोड, 1952 के अंतर्गत उपयुक्त समय पर न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी, तो कम से कम सरकारी पेंशन नियम, 1950 की सहायता लेना न्याय हित है ताकि यह माना जा सके कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रवेश बिंदु पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। [पैरा 15] [181-जी-एच; 182-ए-बी]

3. मान लीजिए, इस मामले में, जब अपीलार्थी ने सेवा में प्रवेश किया था, वह 15 वर्ष और 6 महीने का था और उसने वयस्क होने की आयु प्राप्त नहीं की थी और पेंशन नियम, 1950 के संदर्भ में प्रवेश बिंदु पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और एक तार्किक परिणाम के रूप में निर्गम बिंदु के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 60 वर्ष है, सेवा की कुल अवधि जो कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रदान कर सकता है। 42 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और जब कोई असंदिग्ध आत्म स्पष्ट प्रावधान होता है, तो इसके विपरीत या असंगत या बेमेल कुछ भी, किसी भी परिपत्र या संकल्प या आदेश का नियमों की योजना में निहित अधिकार को कम करने के लिए कोई कानूनी और वैध प्रभाव नहीं होगा। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 को देखते हुए समिति के अभिलेख में दर्ज अपनी जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने का अधिकार है। नियमों की योजना से यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति की आयु

बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगा और व्यक्ति को पेंशन नियम, 1950 को ध्यान में रखते हुए 42 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता है। तत्काल मामले में, नियमों की उस योजना के अलावा, जिसका एक संदर्भ दिया गया है, अपीलकर्ता वयस्कता प्राप्त करने की आयु से कम की सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता है, यदि बिहार सेवा संहिता के तहत प्रवेश स्तर पर न्यूनतम आयु का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा कि अनुरोध किया गया है, अलगाव में स्वीकार किया जाता है और प्रवेश स्तर पर आयु को खुला छोड़ दिया जाता है, तो यह एक ऐसे चरण की ओर ले जाएगा जहां किसी भी उम्र का बच्चा या नाबालिग सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश करने की अपनी पात्रता का दावा कर सकता है जो स्पष्ट रूप से अतार्किक और कानून में अस्वीकार्य है। [कंडिकाएँ 16,18,20] [182-सी-डी; 184-सी; 185-डी-ई]

> रागजावा नारायण मिश्रा और अन्य बनाममुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और अन्य। 2006 (1) पी. एल. जे. आर. 410-अनुमोदित।
>
> नागालैंड वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ एवं अन्य बनाम नागालैंड राज्य और अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 643: [2010] 7 एस. सी. आर. 630-संदर्भित।

इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति के अनुसारः

अभिनिर्धारित कियाः1.1 बिहार राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 15 जनवरी 1998 को जारी सरकारी परिपत्र के अनुसार, बिहार सरकार के तहत किसी निम्न सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। उक्त परिपत्र, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है, जो याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लगभग 18 वर्ष बाद जारी किया गया था उतरगामी और उक्त परिपत्र जारी होने के बाद की गई नियुक्तियों पर ही लागू होती थी। [पैरा 4] [186-ई] ए

1.2 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित होती हैं। बिहार सेवा संहिता का नियम 73 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि "एक सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जिस पर वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद सार्वजनिक आधार पर राज्य सरकार के मंजूरी से सेवा में बनाए रखा जा सकता है, जिसे लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए।" 15 जनवरी 2004 को, बिहार स्कूल परीक्षा समिति ने उन अधिकारियों की सेवा में प्रवेश की आयु, जो सेवा में शामिल होने के समय 18 वर्ष से कम थे, को उनकी नियुक्ति के समय 18 वर्ष मानने का संकल्प लिया। उक्त संकल्प के अनुसार, जिन कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला माना जाना था और यदि वे श्रेणी-4 के कर्मचारी हैं तो वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर और श्रेणी-3 के कर्मचारी होने पर 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे।बाद में, अपीलार्थी की सेवा के दौरान श्रेणी-3 के कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई। [कंडिका 5,6,8] [186-जी-एच; 187-ए-जी]

1.3 संकल्प को पूरी तरह से शब्दबद्ध नहीं किया गया होगा। यह संकल्प पैसे कर्मचारियों के हित में फायदेमंद था जो अन्यथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए पेंशन लाभों से वंचित होते। ऐसे कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष माना जाना था, ताकि वे अपनी सेवा अवधि के हिस्से के लिए पेंशन लाभ से वंचित न रह जाएं, लेकिन बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएं। 15 जनवरी 1998 को जारी संकल्प के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की अनियमित नियुक्तियों के कारण भी उनकी नियुक्ति की वैधता के संबंध में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए संकल्प की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि संकल्प का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु पूरी होने से पहले सेवानिवृत्ति करना था जिन्होनें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के

पूर्व नौकरी की थीयदि यह संकल्प का इरादा होता, तो संकल्प की भाषा और/या शब्दरचना अलग रही होती। [कंडिका 9,10] [187-एच; 188-ए-सी]

2. बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख बिहार सेवा संहिता के नियम 73 द्वारा शासित होती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने का कोई निर्णय कानून के अनुसार बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में संशोधन किए बिना नहीं लिया जा सकता था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक संकल्प के द्वारा बिहार सेवा संहिता के किसी भी प्रावधान में बदलाव का कोई प्रश्न नहीं उठता। अपीलार्थी की नियुक्ति के बाद नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का कोई भी निर्देश, अपीलार्थी पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। [कंडिकायें 11,13] [188-एफ-जी; 189-डी]

3.1 केवल यह तथ्य कि एक कर्मचारी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय नाबालिग हो सकता है, उसकी नियुक्ति के भौतिक समय पर किसी भी कानून के अभाव में महत्वहीन है। 15/16 वर्ष के नाबालिगों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करना किसी भी कानुन के अभाव मे महत्वहीन है ।अपीलार्थी जो साढे पन्द्रह साल का था, नाबालिग हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बच्चा नहीं था।यह हास्यास्पद तर्क है कि कोई भी तर्कसंगत नियोक्ता,एक वैधानिक निकाय तो दूर एक बच्चे को नियुक्त करेगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से भविष्य में नियुक्ति के दावों की आशंका है।15 जनवरी 1998 के परिपत्र को देखते हुए भी आधारहीन है जो सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है। परिपत्र बाद की नियुक्तियों को नियंत्रित करेगा। यह सच हो सकता है कि एक नाबालिग अनुबंध में प्रवेश करने में अक्षम है। किसी नाबालिग के विरुद्ध एक अनुबंध लागू नही किया जा सकता है। नाबालिग द्वारा निष्पादित अनुबंध नाबालिग के विकल्प पर अमान्य हो सकता है। अवयस्क बालिग होने पर अनुबंध का खंडन या अनुसमर्थन कर सकता है और अनुबंध को स्वीकार कर सकता है।यह किसी का मामला नहीं है कि संबंधित कर्मचारियों में से किसी ने भी व्यस्कता प्राप्त करने पर अपनी नियुक्ति के अनुबंध को अस्वीकार कर दिया।एक नियोक्ता जो जानबूझकर अपनी

आंखें खुली रखते हुए नाबालिगों की नियुक्ति करता है, वह रोजगार के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से बच नहीं सकता, और वह भी उस कर्मचारी द्वारा व्यस्कता प्राप्त होने के बाद लगभग दो दशकों तक सेवा प्रदान करने के बाद।यह कहा जा सकता है कि अनुबंधों को संबंधित कर्मचारियों द्वारा व्यस्कता प्राप्त करने पर अनुमोदित किया गया था। [कंडिका 22,23,24] [192-बी-एफ]

3.2 रागजावा नारायण मिश्रा के मामले में, पूर्ण पीठ यह समझने में विफल रही कि 1998 के परिपत्र में उन नियुक्तियों के लिए आवेदन का कोई तरीका नहीं हो सकता है जो उक्त परिपत्र जारी होने से पहले ही की जा चुकी थीं, और निश्चित रूप से उपरोक्त परिपत्र जारी होने से लगभग दो दशक पहले की गई नियुक्तियों के लिए नहीं, ऐसे समय में जब स्वीकार्य रूप से सरकारी सेवा में नियुक्तियों के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं थी। यह मानते हुए भी कि पेंशन लाभों के लिए सरकारी सेवा की कुल अवधि नियम 73 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख और 58/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बीच की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है, इसका मतलब यह होगा कि पेंशन लाभों की गणना 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवा की अवधि के आधार पर की जानी चाहिए।किसी भी मामले में एक कर्मचारी को 58 और/या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित है। [कंडिका 29] [193-ई-जी]

3.3 रगजावा नारायण मिश्रा मामले में पूर्ण पीठ का यह निष्कर्ष कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से लागू होगी और किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद जारी नहीं रखा जा सकता है, यह अपवाद नहीं है। बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में बने रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। हालाँकि, चूंकि सेवा की अवधि लागू नियम के तहत सेवानिवृति के लिए एक मानदंड नही है यानि कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के तहत, एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा अभिलेख में दर्ज अपनी वास्तविक जन्म तिथि के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु पूरी

नहीं की थी, उसे 40 वर्ष से अधिक की सेवा या 40 वर्ष सेवा के पूरा होने के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि चालीस वर्ष मानी जाएगी। सेवानिवृत्ति लाभ के उद्देश्य से सेवानिवृत्ति की आयु और योग्यता सेवा एक ही नहीं है। सेवानिवृत्ति के लिए योग्यता सेवा का अर्थ है कि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से सेवा की अवधि पेंशन की योग्यता सेवा की आयु प्राप्त करने से शुरू होगी। इस प्रकार, यदि सेवा लाभ के लिए योग्यता सेवा की आयु 18 साल है, पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि की गणना 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से करनी होगी। हालांकि, यदि सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 60 वर्ष पूरी करना होता है, तो किसी कर्मचारी को सेवा नियमों में प्रदान किए गए आधार के अलावा उस आयु से पहले सेवानिवृत्त के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 30,32,33] [193-एच; 194-ए-एफ]

रागजावा नारायण मिश्रा और एक अन्य बनाम प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग समिती और अन्य 2006 (1) पी. एल. जे. आर. 410-अस्वीकृत।

अतिबाड़ी चाय कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 232:[1961] एस. सी. आर. 809; जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1260; गणेश राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2006 (2) एफ. एल. आर. 156-संदर्भित।

मामले का कानूनी संदर्भ

अजय रस्तोगी न्यायमूर्ति के अनुसारः

2006 (1) पीएलजेआर 410	मंजूरी मिल गई	कंडिका 8
[2010] 7 एस. सी. आर. 630	संदर्भित किया गया है	कंडिका 19

इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति अनुसारः

2006 (1) पीएलजेआर 410	अस्वीकृत	कंडिका 21
[1961] एससीआर 809	संदर्भित किया गया है	कंडिका 34
(2016) एस.सी.सी. ऑनलाइन 1260	संदर्भित किया गया है	कंडिका 34
2006 (2) एफएलआर 156	संदर्भित किया गया है	कंडिका 37

दीवानी अपीलीय न्यायाधिकारः-सिविल अपील सं. 8225/2012

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1090/2012 पटना उच्च क्षेत्राधिकार द्वारा पारित दिनांकित 03.08.2012 के निर्णय और आदेश से।

आनंद शंकर झा, अर्जुन गर्ग, श्रीकांत एस., मनीष कुमार और गोपाल सिंह, उपस्थित पक्षो के अधिवक्तागण गोपाल प्रसाद बनाम बिहार विद्यालय परिक्षा समिति और अन्य।

न्यायालय के निर्णय न्यायमूर्ति रसतोगी द्वारा पारित

निर्णय

मैंने अपने सम्मानित भाई के द्वारा तैयार किए गए निर्णय के मसौदे को पढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस बात से सहमत नहीं हो पाया हूं कि अपील खारिज कर दी जानी चाहिए।

2. अपील पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 3.8.2012 को पारित एक आदेश के विरुद्ध है, जिसमें 2012 की लेटर पेटेंट अपील संख्या 1090 को खारिज करते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर 2012 की रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी

संख्या 7718 को खारिज करते हुए एकल पीठ के दिनांक 24.4.2017 के आदेश की पुष्टि की गई थी ।

3. अपीलकर्ता को 20 मई, 1970 को लगभग 15 वर्ष की उम्र में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के सुलेख-सह-सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।यह विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता में नियुक्ति तारीख, अर्थात् 20 मई, 1970 को सुलेख-सह-सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी.हालाँकि पेंशन प्राप्त करने योग्य सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी।इसका अर्थ यह हुआ कि 16 वर्ष की आयु से पहले कर्मचारी की सेवा की अवधि को पेंशन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. बिहार राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 15 जनवरी, 1998 को जारी एक सरकारी परिपत्र द्वारा बिहार सरकार के अधीन अवर सेवा अंतर्गत नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।कथित परिपत्र, जिसमें नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु १८ वर्ष निर्धारित की गई थी, जो याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लगभग १८ वर्ष बाद जारी हआ था, जो केवल उन पर लागू होती थी जिनकी नियुक्तियां परिपत्र जारी करने के बाद की गई ।

5. बिहार विद्याालय परिक्षा समिति कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित हैं। बिहार सेवा कोड के नियम 73 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि “सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह तिथि है जिस दिन वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद सार्वजनिक आधार पर राज्य सरकार के मंजूरी से सेवा में बनाए रखा जा सकता है, जिसे लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए।"

6. 15 जनवरी, 2004 को बिहार विद्यालय परिक्षा समिति ने सेवा में प्रवेश की आयु, जो सेवा में शामिल होने के समय 18 वर्ष से कम आयु के थे, उनकी नियुक्ति के समय 18 वर्ष करने का संकल्प लिया।

7. प्रस्ताव का प्रासंगिक अंश, जैसा कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, सुविधा के लिए यहां नीचे दिया गया है:-

> "आज दिनांक 15 जनवरी, 2004 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक अध्यक्ष के कक्ष में आयोजित की गई।जिसमें डॉ. जितेन्द्र सिंह, कुलाधिपति पटना विश्वविद्यालय और श्री सुभाष चन्द्र चौधरी, सहायक शिक्षक, सीएम उच्च स्कूल, सीवान ने अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के रूप में भाग लिया।
>
> कार्यवाहियां
>
> कार्य सूची संख्या - 1
>
> कार्य सूची संखया - 2

समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के संबंध में	समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के बारे में 18 नवम्बर, 2003 को आयोजित समिति की बैठक में दिए गए निर्णय के आलोक में प्राप्त कानूनी सलाह के विश्लेषण के बाद, माननीय सदस्य डॉ. जितेन्द्र सिंह, कुलाधिपति, पटना ने सूचित किया कि उच्च शिक्षा विभाग, बिहार के सचिव से पत्र संख्या 1961 दिनांक 12.11.1995 के अंतर्गत भी समिति में कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। उपर्युक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 18 वर्ष से कम आयु में की गई है और उनकी नियुक्ति की तिथि तक उनकी आयु 18 वर्ष है, उन्हें श्रेणी-4 के मामले में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर और श्रेणी-3 के मामले में 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा।

8. उपर्युक्त संकल्प को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त किया गया था, उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला माना जाएगा और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे यदि वे श्रेणी-4 के कर्मचारी हैं और यदि वे श्रेणी-3 के कर्मचारी हैं तो 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होगे। 58 वर्ष की आयु को श्रेणी-3 के कर्मचारियों को बाद में अपीलकर्ता की सेवा अवधि के दौरान बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया।

9. हो सकता है कि संकल्प पूरी तरह शब्दो में न लिखा गया हो। मेरे विचार से, यह संकल्प उन कर्मचारियों के हित में लाभदायक था, जो अन्यथा 18 वर्ष की आयु से पहले अपनी सेवा की अवधि के लिए पेंशन लाभों से वंचित हो जाते।ऐसे कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष माना जाना था, ताकि वे अपनी सेवा अवधि के हिस्से के लिए पेंशन लाभ से वंचित न रह जाएं, लेकिन बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएं। 15 जनवरी 1998 को जारी संकल्प के बाद से कम उम्र के व्यक्तियों की अनियमित नियुक्तियों के कारण भी उनकी नियुक्ति की वैधता के संबंध में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए संकल्प की आवश्यकता हो सकती है ।ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि संकल्व का उदेश्य उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना था जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में शामिल हूए थे, उनकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु पूरी होने से पहले, नियम के अनूसार ।

10. यदि प्रस्ताव का इरादा यह होता कि 18 वर्ष की आयु प्राप्ति से पहले नियुक्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के अनुसार, प्रस्ताव की भाषा और/या शब्द अलग होते।प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 18 वर्ष की आयु से पहले नियुक्त कर्मचारियों की जन्मतिथि को सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए उस तारीख के रूप में माना जाएगा जिस तारीख को संबंधित कर्मचारी का जन्म हुआ था, यदि वह नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी करता है।संकल्प में स्पष्ट रूप से कहा

गया है कि ऐसे कर्मचारी बिहार सेवा संहिता में निधारीत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उनकी मानी हुई जन्म तिथि के अनूसान सेवानिवृत्त होगें, इस तथ्य के वावजूद कि उन्होने विहार विद्यालय परिक्षा समिति के अनूसार सेवा निव्रति कि आयु प्राप्त नही की है ।

11. जैसा कि ऊपर कहा गया है बिहार परीक्षा समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख बिहार सेवा संहिता के नियम 73 द्वारा शासित है। 8 वर्ष की आयु से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने का कोई निर्णय बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में कानून के अनुसार संशोधन किए बिना नहीं लिया जा सकता था।बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक प्रस्ताव के द्वारा बिहार सेवा कोड के किसी भी संकल्प में बदलाव का कोई प्रश्न नहीं उठता।

12. 14 फरवरी 2004 को अपीलकर्ता को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसकी अंतवस्तु, जैसा कि अनुवाद किया गया है, नीचे दी गई हैः-

> “श्री गोपाल प्रसाद को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 18 वर्ष से कम आयु में नियुक्ति मिली, किसी भी सरकारी (अर्ध-सरकारी) स्वायत्तशासी संस्थान में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।बिहार विद्यालय परिक्षा समिति में 15 जनवरी, 2004 को हुई बैठक में यह फ़ैसला लिया गया था कि नियुक्ति में तारीख तक उनमें आयु 18 वर्ष है उनहे 60 वर्ष की उर्म में सेवानिवृत्त किया जाएगा अगर वे श्रेणी-4 में है और श्रेणी-3 के मामले में 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हे सेवानिवृत्त किया जाएगाा ।
>
> इसलिए, श्री गोपाल प्रसाद सहायक का सहायक की आयु 18 वर्ष को उनकी नियुक्ति की तारीख अर्थात 27.05.1970 मानते हुए, निर्देशाानुसार, सेवा पूस्तिका में उनकी सेवानिवृत्ति की

तारीख 31.05.2010 दर्ज करने का आदेश जारी किया जाता हैं।"

13. दिनांक 14 फरवरी, 2004 का आदेश, जहां तक अपीलकर्ता की सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तारिख 31 मई 2010 दर्ज करने का तात्पर्य है, बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के विपरीत है और बिहार सेवा संहिता के दाये और दायरे से परे भी है जो 15 जनवरी, 2004 को संकल्प लिया गया है ।अपीलकर्ता की नियुक्ति के बाद नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का कोई भी नुस्खा, पूर्वव्यापी रूप से अपीलकर्ता पर लागू नहीं किया जा सकता था.

14. इस अपील के संबंध कहा दायर याचिकओं से, यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता ने 14 फरवरी, 2004 के कथित कार्यालय आदेश पर आपत्ति जताई थी या नहीं।किसी भी मामले में एक कार्यालय आदेश जो स्पष्ट रूप से गैरकानूनी है और हानिकार नागरिक परिणाम लाता है, इस आधार पर चुनौती से वंचित नहीं किया जाता है कि पीड़ित कर्मचारी ने कार्यालय के आदेश पर आपत्ति नहीं की होगी, और इससे भी अधिक, जब इसी तरह के आदेशों की वैधता उच्च न्यायालय में अधिनिर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। विभिन्न रिट याचिकाएं लंबित थीं उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर कि क्या 18 वर्ष की आयु से पहले सेवा में शामिल होने वाले व्यक्तियों को बिहार सेवा नियमों के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले एकतरफा रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई समझी जानी थी।अभिलेख में यह भी एक बात है कि इनमें से कई रिट याचिकाओं का फैसला कर्मचारियों पक्ष में किया गया था, जिनके उदाहरण इस फैसले में बाद में दिए गए हैं।

15. यह विवाद में नहीं है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अभिलेख के अनुसार अपीलकर्ता में जन्म तिथि 19 नवंबर, 1954 है. यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि, जैसा कि दर्ज किया गया है, 19 नवंबर, 1954, उसकी सही जन्म तिथि नहीं है.

16. अपीलकर्ता की जन्म तिथि 19 नवम्बर, 1954 थी और उसे 19 नवम्बर, 2012 को 58 वर्ष की आयु पूरी करनी थी।हालांकि 18 नवंबर 2012 से पहले सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी।अपीलकर्ता की जन्म तिथि 19 नवम्बर, 1954 थी, उसे 18 नवम्बर, 2014 को साठ वर्ष की आयु पूरी करनी थी।

17. जैसा कि ऊपर कहा गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सेवा में अपीलकर्ता की नियुक्ति से बहुत पहले, बिहार पेंशन नियमों के परिशिष्ट-5 में नियम 5 में संशोधन किया गया था।पेंशन संबंधी लाभों पर विचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की पात्रता आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। हालाँकी, सरकारी प्राधिकारियों ने ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करना जारी रखा जिन्होने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी ।

18. 16 फरवरी, 2012 को या उसके लगभग, अपीलकर्ता के पुत्र ने सूचना का अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसके पिता की सेवानिवृत्ति के लिए समिति द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख के बारे में पूछताछ की गई।

19. 26 मार्च, 2012 के एक पत्र द्वारा समिति ने अपीलकर्ता के पुत्र को सूचित किया कि 14 फरवरी, 2004 के फैसले को ध्यान में रखते हुए, 27 मई, 1970 को अपीलकर्ता की आयु को 18 वर्ष माना गया था और इसलिए उसका सेवानिवृत्ति 58 वर्ष पूरे होने पर 31 मई, 2010 को होनी थी, जो बाद में बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मई, 2012 होगी।

20. इसके बाद, अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहद दिनांक 20 मार्च, 2012 को भेजे गए पत्र और 14 फरवरी, 2004 को जारी आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में याचिका संख्या सीडब्ल्यू जे सी 7718/2012 दायर किया।

21. 24 अप्रैल 2012 के एक आदेश द्वारा, एकल पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, रिट याचिका को खारिज कर

दिया राघव नारायण मिश्रा और अन्य बनाम बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य[1] पटना उच्च की पूर्ण पीठ अदालत ने कहाः-

> "16. चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने जब प्रतिवादी समिति के साथ अनुबंध किया था तो वे वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर पाए थे।"इसके कानूनी प्रभाव और प्रभाव के अलावा, सेवा संबंध के संदर्भ में, एक अनुबंध की स्थिति पर प्रभाव और अंतिम परिणाम के बारे में कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने वैध सेवा में प्रवेश किया है, केवल तभी जब वह वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है।इसलिए सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।निकाश बिन्दू के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है।दूसरे शब्दों में, पेंशन लाभ के लिए किसी भी मामले में सरकारी सेवा की कुल अवधि 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस संदर्भ में ऊपर उल्लिखित सरकारी परिपत्र पर विचार करने की आवश्यकता है।जब कोई स्पष्ट नियम प्रावधान हो, जो इसेके विपरीत या असंगत है तो किसी परिपत्र या प्रस्ताव या आदेश में कोई कानूनी और वैध प्रभाव नहीं होगा। यहां तक कि अगर 1988 के उक्त परिपत्र को याचिकाकर्तओ के भरोसे के रूप में उनके लिए फायदेमंद माना जाता है, तो भी इस बिहार पेंशन नियमों के साथ-साथ बिहार सेवा संहिता में शामिल किए गए मौजूदा वैधानिक प्रावधान के साथ संयोजन नही पढा जा सकता है। इसलिए, उस दृष्टिकोण से भी, याचिकाकर्ताओं को यह प्रतिवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्हें 58 वर्ष की आयु के बाद भी पद पर बने रहने का अधिकार है, हालांकि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में इसका प्रावधान है, जो 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है।

---

1 2006 (1) पीएलजेआर 410

17. तीसरा, इसने कानून और न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के प्रस्ताव को स्थापित ओर स्थापित किया कि एक व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश बिंदु पर एक या अन्य कारणों से अनुचित लाभ उठाता है, उसे यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे उच्च लाभ दिया जाए और यदि यह स्पष्ट रूप से आग्रह किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि सेवा में प्रवेश बिंदु पर कुछ गलत या अनियमित किया गया है।इस प्रकार, स्थापित सिद्धांत भी इस न्यायालय से राहत प्राप्त करने में एक बहुत मजबूत बाधा पैदा करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधान का आह्वान द्वारा असाधारण, विशेषाधिकार, न्यायसंगत और विवेकाधीन रिट श्रेत्राधिकार का उपयोग कर रहा है।

18. इसलिए, हमारी राय में दोनों रिट याचिकाओं में विवादित आदेशों में, स्पष्ट रूप से, किसी भी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है।इसलिए कानून के प्रस्ताव को इस बात का स्पष्ट प्रमाण माना जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित अधिवर्ष्तिा आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और एक व्यक्ति को सेवा में 40 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी जारी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने 40 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसे मौजूदा नियम प्रावधान के अनुसार अधिवर्ष्तिा प्राप्त करनी होगी ।इसलिए हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट है और हम इस संदर्भ के अनुसार उत्तर देते हैं।यहा इसके पूर्व निर्दिष्ट पूर्वोक्त निर्णयों में विरोधाभासी दृष्टिकोण एक अच्छा कानून नहीं होगा।"

22. केवल तथ्य यह है कि कोई कर्मचारी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय अवयस्क हो सकता है, उसकी नियुक्ति के समय किसी भी कानून के अभाव में 15-

16 वर्ष पहले के नियुक्ति पर रोक लगाना अप्रासोगिक है। अपीलकर्ता, जो 15 साल का था, एक अवयस्क हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक बच्चा नहीं था.यह हास्यास्पद तर्क है कि कोई भी तर्कसंगत नियोक्ता, जो वैधानिक निकाय नहीं है, एक बच्चे को नियुक्त करेगा।एक बच्चे की नियुक्ति की परिकल्पना बहुत दूर और अवास्तविक है। भविष्य में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों कि नियुक्ति के दावों की आशंका भी निराधार है क्योंकि दिनांक 15 जनवरी, 1998 के परिपत्र में सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। परिपत्र बाद की नियुक्तियों को नियंत्रित करेगा।

23. यह सच हो सकता है कि एक अवयस्क एक अनुबंध करने में अक्षम है, जैसा कि मेरे सम्मानित भाई द्वारा देखा गया है।कोई अनूबंध का खंडन अवयस्क के विरूद्व लागू करने योग्य नही हो सकता है। अवयस्क द्वारा निष्पादित अनुबंध अवयस्क के विकल्प पर अमान्य करणीय हो सकती है। अवयस्क बालिग होने पर अनुबंध का खंडन या अनुसमर्थन कर सकता है और अनुबंध को स्वीकार कर सकता है।

24. यह किसी का मामला नहीं है कि संबंधित कर्मचारियों में से किसी ने भी बालिग होने पर अपनी नियुक्ति की अनुबंध को अस्वीकार कर दिया। एक नियोक्ता जो जानबूझकर अपनी आंखें खुली रखते हुए नाबालिगों की नियुक्ति करता है, वह रोजगार के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से बच नहीं सकता, और वह भी उस कर्मचारी द्वारा व्यस्कता प्राप्त होने के बाद लगभग दो दशकों तक सेवा प्रदान करने के बाद।यह कहा जा सकता है कि संविदाओं का अनुमोदन संबंधित कर्मचारियों द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर किया गया है।यह भी नहीं कहा जा सकता कि 15 साल की उम्र में नियुक्त कर्मचारी ने कोई अनुचित लाभ हासिल किया जबकि उस समय पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं थी।

25. विद्वत एकल न्यायाधीश ने राघव नारायण मिश्रा (उपर्युक्त) की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया और खंड पीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय से अपील को खारिज कर दिया।विद्वान एकल पीठ

के साथ-साथ विद्वान खंड पीठ के पास कोई नहीं था राघव नारायण मिश्रा (उपर्युक्त) का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नही था, क्योकि न्यायिक अनुसरण के लिए पूर्ण पीठ के निर्णय का पालन करने के लिए कम शत्तिवाली पीठों की आवश्यकता होती है ।

26. मेरे विचार से, राघव नारायण मिश्रा (उपर्युक्त) में बिहार सेवा संहिता के नियम 73 पुर्ण पीठ की व्याख्या गलत और त्रुतीपुर्ण है ।अपीलार्थी की ओर से पेश हुए वकील ने सही तर्क दिया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो सेवानिवृत्ति के लिए मानदंड के रूप में सेवा की अवधि को निर्धारित करता है.बिहार विद्यालय संहिता के नियम 73 और बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 57 में सेवा की अवधि के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

27. पूर्ण पीठ ने सेवा काल के आधाार पर कार्यवाही करने में गलती की, जब बिहार सेवा का संहिता 73 अध्विषर्ता की एक विशिष्ट आयू निर्धारित करती है । कोड सेवानिवृत्ति की एक विशिष्ट आयु निर्धारित करती है। जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है, बिहार सेवा कोड का नियम ७३ सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है.उक्त नियम सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को एक मानदंड नहीं बनाता है।

28. पेंशन प्राप्त करने योग्य सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम अर्हता आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का अर्थ है कि यदि कोई कर्मचारी 18 वर्ष की आयु से पहले सेवा में प्रवेश करता है, तो नियुक्ति की वास्तविक तिथि से पेंशन योग्य सेवा के लिए अर्हता आयु प्राप्त करने तक नौकरी अवधि को पेंशन/पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा।

29. राघव नारायण मिश्रा (ऊपर) में पूर्ण पीठ इस बात को स्वीकार करने में विफल रही कि 1998 के परिपत्र में उक्त परिपत्र के जारी होने से पहले की गई नियुक्तियों के लिए आवेदन करने का कोई तरीका नहीं था, और निश्चित रूप से उपरोक्त परिपत्र जारी होने से लगभग दो दशक पहले की गई नियुक्तियों के लिए, ऐसे

समय में जब निश्चित रूप से सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं थी। यह मानते हुए भी कि सरकारी सेवा का कुल कार्यकाल नियम 73 के अनुसार पेंशन लाभ के लिए सेवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने और 58/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बीच की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ यह होगा कि पेंशन लाभ की गणना 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवा की अवधि के आधार पर की जाएगी।बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित 58 और/या 60 वर्ष की आयु से पहले किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है।

30. रग्जावा नारायण मिश्रा (उपरोक्त) मामले में पूर्ण न्यायपीठ का निष्कर्ष कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में विहित अधिवर्षिता आयु सेवानिवृत्ति के उदेश्य के लिए लागू होगी और सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद व्यक्ति को जारी नहीं रखा जा सकता है, अपवादात्मक नहीं है।किसी भी परिस्थिति में कोई भी सरकारी सेवक बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु पुरी होने के बाद सरकारी सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता। हालांकि, चूंकि लागू नियम के अंतर्गत सेवा की अवधि सेवानिवृत्ति के लिए एक मानदंड नहीं है, जो कि बिहार सेवा संहिता का नियम 73 है, एक सरकारी कर्मचारी जिसने अपनी वास्तविक आयु सेवा अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु पूरी नहीं की थी। 40 वर्ष से अधिक की सेवा या सेवा के पूरा होने के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है।पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि को अधिकतम चालीस वर्ष माना जाएगा।

31. पूर्ण पीठ के संबंध मे, मैं बिहार पेंशन नियमावली के परिशिष्ट-5 के नियम 5 से सहमत नही हो पा रहा हूँ जिसमें पेंशन लाभ पर विचार करने हेतु कर्मचारी की पात्रता आयु निर्धारित करने और/या ऐसी आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने से बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु में कोई अंतर पड़ता है।

32. सेवानिवृत्ति की आयु और सेवानिवृत्ति लाभो के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा एक और समान नही है ।सेवानिवृत्ति के लिए अर्हक सेवा का अर्थ है कि

सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से सेवा की अवधि पेंशन की अर्हक सेवा की आयु प्राप्त करने से शुरू होगी।

33. इस प्रकार, यदि पेंशन के लिए अर्हक सेवा की आयु 18 वर्ष है पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि की गणना 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी।हालांकि, यदि सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है, तो किसी कर्मचारी को सेवा नियमों में प्रदान किए गए आधार के अलावा उस आयु से पहले सेवानिवृत्त के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को अनुशासनात्मक कारवाई के माध्यम से समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है, यदि नियमों में ऐसा प्रावधान है।

34. जब सेवानिवृत्ति की आयु नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। जो सेवानिवृत्ति के मानदंड के रूप में सेवा की अवधि को निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन आयु प्राप्त होने पर सेवानिहति का प्रावधान करते हैं, किसी कर्मचारी को सेवानिहति की उस आयु को प्राप्त करने से पहले सेवानिहत नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि उसने तार्किक तर्क की एक जटिल प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए सेवा की है, मेरा न्यायिक विवेक भी मुझे अपील के अंतर्गत फैसला को कायम रखने की अनुमति नहीं देता है, केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय ने कुछ समय के लिए उस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले का पालन किया है जिसने कुछ समय के लिए क्षेत्र को बरकरार रखा है। मेरी राय में पूर्ण पीठ का निर्णय गलत था।इस न्यायालय के पास समय है और फिर से अपने फैसलों को पलट दिया, जिसमें संवैधानिक पीठों के फैसले भी शामिल थे, जो दशकों से इस क्षेत्र में रहे हैं। एक उदाहरण का हवाला देने के लिए, अतियाबारी टी कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य[2] जिसने लगभग आधि सदी तक इस क्षेत्र को संभाला था उसे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य[3] वाले मामले में नौ न्यायाधीशों ने अस्वीकार कर दिया था। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि क्यों नही आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

---

2 एयर 1961 एससी 232

3 2016 एससीसी ऑनलाइन 1260 11.11.2016 को तय किया गया

35. बिहार सेवा संहिता के नियम 73, जो केवल अधिवर्षिताकी आयु निर्धारित करता है और क्या पूरा होने के बाद, ऐसे किसी नियम के अभाव में भी 40 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक सरकारी कर्मचारी को सेव में प्रवेश के समय उसकी आयु 18 वर्ष मानते हुए सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, झारखंड न्यायालय न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय के एक खंडपीठ द्वारा गणेश राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य में विचार किया था। राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य संख्या डब्ल्यूपी (एस) 2003 की डब्ल्यू पी (एस) संख्या 1210, 2006 (2) एफएलआर 156 में बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के संदर्भ में रिपोर्ट किया गयाबिहार सेवा संहिता बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार सृजित झारखंड राज्य में लागू है और इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो पहले बिहार राज्य में थे।इन मुद्दों का कर्मचारियों के पक्ष में और झारखंड राज्य तथा अन्य के खिलाफ नकारात्मक जवाब दिया गया।गणेश राम (उपर्युक्त) के निर्णय की एक प्रति भी पेपर बुक के साथ संलग्नक पी-5 के रूप में संलग्न की गई है।

36. गणेश राम (उपर्युक्त) वाले मामले में न्यायालय ने सही पाया कि बिहार राज्य द्वारा राज्य के सेवा में या झारखंड राज्य में नियुक्ति के लिए कोई समान न्यूनतम आयु 18 वर्ष विहित नहीं की गई थी।न्यूनतम योग्यता आयु एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए अलग-अलग है।अदालत ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित कियाः-

> “7. अधिनियम की धारा 2 (i) के अंतर्गत 'कर्मचारी' की परिभाषा का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जिसे किराए पर या पुरस्कार के लिए या कोई भी काम, कुशल या अकुशल, करने के लिए नियोजित है और इसमें उचित सरकार अर्थात राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारी भी शामिल है। धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित किया गया है अर्थात '' किशोर '' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपनी चौदहवीं वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु अपनी अठारहवीं वर्ष पूरी कर चुका हो "वयस्क" "को धारा 2 के खंड

(एए) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, जिसने अपनी अठारहवीं वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जीसकी धारा 2 के खंड (बीबी) के अंतर्गत परिभाषित" "बच्चा" से वह व्यक्ति, जिसने अपनी चौदहवीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।" "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 में उस तरीके का उल्लेख किया गया है जिसमें उपयुक्त सरकार मजदूरी की न्यूनतक दरो को तय करेगी उपखंड (3) के अंतर्गत उचित सरकार को वयस्कों, किशोरों, बच्चों और प्रशिक्षुओं के लिए मजदूरी की विभिन्न न्यूनतम दरें तय करने का अधिकार है।इससे पता चलता है कि सरकारी नौकरी में भी एक किशोर की नियुक्ति की जा सकती है, भले ही वह अवयस्क हो, जिसके लिए अलग-अलग मजदूरी तय में जा सकती है।"

हाईकोर्ट ने आगे कहाः

8. बिहार राज्य ने पुलिस आदेश संख्या 209-82 जारी किया है, जिसे ज्ञापन संख्या 6568/पी2/43-271-88, दिनांक 11 अगस्त, 1988 द्वारा परिचालित किया गया है।बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 के मद्देनजर यह पुलिस आदेश झारखंड राज्य में भी लागू है।इस आदेश के अनुसार, पुलिस बल की स्वीकृत संख्या में दो पद आरक्षित किए जा सकते हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के पुलिस बल के आश्रित बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, यदि कर्तव्य के दौरान किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है।इस प्रकार नियुक्त किए गए बच्चों को अमूमन बाल-अराक्षी के रूप में जाना जाता है और उन्हें वयस्क होने तक वार्षिक वेतन वृद्धि के बिना पद के न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है।केवल सहमती होने पर, यदि बाल-अराक्षी की इच्छा और अर्हता होती है, तो उन्हें ऐसे पदों से

कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाता है।नियुक्ति पर अवस्यक को दो आधे पैंट, दो शर्ट, दो जोडीी मोजे, एक जोड़ी जूते आदि दिए जाते है । इसमें साफ़ पता चलता है कि राज्य की सेवओं में अवस्यक की नियुक्ती पर कोई रोक नही है ।"

37. निश्चित रूप से, जैसा कि गणेश राम के निर्णय में उल्लेख किया गया है (पूर्वोक्त) बाल रोजगार (प्रतिषेध और विनियमन) कार्य, 1986 के अधिनियमन और प्रवर्तन के पश्चात् किसी बच्च का नियोजन, जिसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, कुछ प्रकार के कार्य के लिए निषिद्ध है।हालांकि, उक्त बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 इस मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उक्त अधिनियम के कार्यन और प्रवर्तन से बहुत पहले नियुक्त किया गया था और किसी भी स्थिति में नियुक्ति के समय वह 14 वर्ष से अधिक आयु का था ।

38. बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में यथा विहित समतुल्य आयु के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे का उत्तर नकारात्मक, नियोक्ता के विरुद्ध और निम्नलिखित गणेश राम (उपरोक्त) के मामलें में कर्मचारी पक्ष में दिया गयाः

1. मोखतार अहमद बनाम बीएसआरटीसी और अन्य (1995 (1) पीएलजेआर 183 (डीबी)

2. मंटू बनाम सीसीएल (2001 (1) जेसीआर 181)

3. कलानंद झा बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2001 (3) जेसीआर 228)

4. बालकेश्वर बनाम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (2002 (1) जेसीआर 175)

5. प्राणधर प्रसाद बनाम झारखंड राज्य और अन्य (मनु/जेएच/1137/2002)

39. मेरा विचार है कि झारखंड उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने गणेश राम (पूर्वोक्त) वाले मामले में कानुन मे सही व्याख्या की है।कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु प्राप्त करने पर ही सेवानिवृत्त हो सकता है जब तक कि नियम स्पष्ट रुप सेवा की अवधि को सेवानिवृत्ति का एक मानदंड नही बनाते हैं, जैसा कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के मामला में होता है, जो विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत 9 सितंबर, 1997 को जारी अधिसूचना, जिसके तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष पूरी करने या 42 वर्ष की सेवा पूरी करने, इनमें से जो भी पहले हो, निर्धारित की गई थी।

40. नगालैंड के वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य (पूर्वोक्त) में मेरे सम्मानित भाई द्वारा संदभिर्त निर्णय मेरे विचार में स्पष्ट रूप से भिन्न् है।39. उपर्युक्त मामले में लागू नियमों में सेवा की निर्धारित अवधि को सेवानिवृत्ति के लिए मानदंड के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

41. इस न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, 1991 से नागालैंड सेवानिवृत्ति की धारा 3 की विधिमान्यता को कायम रखा जिसमें यह उपबंध किया गया थाः-

> “एस-3.सार्वजनिक रोजगार से सेवानिवृत्तिः(1) किसी भी किसी नियम या आदेश के लागू होने के बावजूद, सार्वजनिक रोजगार में एक व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार में शामिल हाने की तारीख् से तैंतीस वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह 57 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, तब तक सेवा में बना रहेगा ।
>
> बशर्ते कि विशेष परिस्थितियों में, सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अधिकतम एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है

> परंतु आगे सरकार, पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक रोजगार में बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए समय-समय पर सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के मामलों की जांच कर सकती है।
>
> (2) सार्वजनिक नियोजन के अधीन सभी व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन कि दोपहर के बाद सेवानिवृत्त होगे, संतावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या तैंतीस वर्ष की सार्वजनिक सेवा पुरी करने पर, जो भी पहले हो,"

42. नगालैंड रोजगार से सेवानिवृत्त (संशोधन) अधिनियम, 2007 (प्रथम संशोधन अधिनियम, 2007) द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई।नागालैंड सार्वजनिक रोजगार से सेवानिवृत्त (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2009) द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा की अवधि 33 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई। इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित कियाः-

> “इस तरह का मुद्दा जो नागालैंड राज्य में सार्वजनिक रोजगार मे 35 साल की सेवा पूरी होने पर या 60 साल की उम्र होने तक, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को मनमानी या अतार्किकता से प्रभावित नहीं करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता है। अपील में कोई योग्यता नहीं है और लागत के बारे में बिना किसी आदेश के इसे खारिज किया जाता है।"

43. जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस मामला में बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में सेवानिवृत्ति के लिए मानदंड के रूप में सेवा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।अपीलकर्ता जिस श्रेणी से संबंधित था, उसके कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 58 वर्ष थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया।सेवा

अभिलेखो में दर्ज उनकी वास्तविक जन्म तिथि के अनूसार 60 पर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपीलकर्ता को सेवानिवृत्त करने के प्रतिवादियो के निर्णय को कायम नही रखा जा सकता है ।

44. मेरा विचार है कि अपील मंजूर की जानी चाहिए और खंड पीठ और एकल पीठ के निर्णय को रद्द कियाा जाता है । रद्द किया जाता है ।अपीलकर्ता इस घोषणा का हकदार है कि अपीलकर्ता 18 नवंबर, 2014 तक सेवा में बने रहने का अधिकारी था, क्योंकि वह उस तारीख को अपने सेवा अभिलेख के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पूरी की थी, और वह अवशिष्ठ बकाये, यदि कोई हो, पेंशन लाभ आदि सहित सभी अहम लाभों का अधिकारी होगा।

45. चूंकि हम सहमत नहीं हुए हैं, इसलिए इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक बडी बेंच को सौपने के लिए रखा जाए।

(इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

28 मई, 2020

निर्णय

रस्तोगी, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के लिए एकल पीठ के 24 अप्रैल, 2012 के निर्णय की पुष्टि करते हुए लेटर पेर्टेंट अपील संख्या 1090 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 3 अगस्त, 2012 को पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित है कि अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से उचित रूप में सेवानिवृत्त किया गया है।

2. वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य जो अभिलेख से प्रकट होते हैं, वह यह है कि अपीलार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कर्मचारी था (इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है) और प्रारंभ में 20 मई, 1970 के आदेश के अनुसार, जिसके अनुसरण में वह 27 मई, 1970 को सेवा सुलेखन सह सहायक के रुप में नियुक्त नियुक्त किया गया था.हालांकि स्कूल अभिलेख के अनुसार अपीलकर्ता की जन्म तिथि १९ नवंबर, १९५४, थी और २७ मई, १९७० को सेवा में प्रवेश करने के समय, वह १५ साल ६ महीने और ८ दिन का था.सेवा में प्रवेश के समय समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। जिसके परिणामस्वरुप समिति ने भी 30 मार्च 2005 को हुई बैठक में अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया ओर उसके अनूसरण में, बोर्ड के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह तिथि बन गई जिस दिन किसी ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की थी ।

3. योग्यता के आधार पर मामले की जांच करने से पहले, इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नियमों के भौतिक प्रक्षेपण पर ध्यान देना उचित होगा।राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं बिहार सेवा संहिता, 1952, बिहार पेंशन नियम, 1950 द्वारा शासित है। सेवानिवृत्ति की आयु बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के तहत निर्धारित की गई है।इसके साथ ही 20 जनवरी, 1950 से प्रभावी बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 57 में पात्रता सेवा निर्धारित की गई है और 23 अगस्त, 1950 से संशोधित पेंशन नियमों की धारा 4 (पात्रता सेवा) के नियम 5 द्वारा इसमें और संशोधन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नियम नीचे दिए गए हैं।

<u>बिहार सेवा कोड, 1952 का नियम 73</u>

> “सरकारी नौकर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह तिथि है जिस दिन वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उसे सार्वजनिक आधार पर राज्य सरकार की मंजूरी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की

तारीख के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है, जिसे लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए।"

बिहार पेंशन नियम, 1950 का नियम 57 20 जनवरी, 1950 से असरदार

"अवर सेवा में एक सरकारी सेवक के लिए, अर्हक सेवा, तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।"

पेंशन नियमों की धारा IV (पात्रता सेवा) का नियम 5 23 अगस्त, 1950 से असरदार

"न्यूनतम आयु जिसके बाद पेंशन के लिए सेवा 16 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष की जाती है एक निम्न सेवा से संबंधित सरकारी सेवक के मामले में (1) जब वह बिहार सरकार की सेवा में प्रवेश करता है, उस तिथि के बाद यह आदेश लागू हआ था या (2) जिसने उस तारीख को या उससे पहले ऐसी सेवा में प्रवेश किया हो उस तारीख को बिहार सरका के अधिक स्थायी पेंशन योग्य पद पर धारणधिकार या निलंवन ग्रहणधिकार नही था ।"

4. इस भरोसा को बिहार राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी 15 जनवरी, 1998 के एक सरकारी परिपत्र द्वारा भी भरोसा जताया गया है।

5. उपर्युक्त प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह स्पष्ट रुप से प्रगट होता है कि पेंशन नियम 1950 में लागू किए गए थे और 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी पेंशन नियम, 1950 के नियम 5 के तहत संशोधन किए जाने के बाद पेंशन के

लिए पात्रता सेवा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो गयी इसमें कोई विवाद नहीं है कि बिहार सेवा संहिता, 1952 के तहत सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी वयस्कता की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में कोई प्रवेश नहीं किया जा सकता है, यानी नियम, 1950 के अंतर्गत निर्धारित 18 वर्ष जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट नियम न हो। सेवानिवृत्ति की आयु को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वर्तमान मामले में 60 वर्ष है, अधिकतम योग्यता सेवा जो कोई प्रदान कर सकता है वह 42 वर्ष की होगी।6. समिति ने 15 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में यह फ़ैसला लिया कि वे लोग जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में प्रवेश किया है, उनकी नियुक्ति की तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष है, मानते हुए श्रेणी 4 के मामले में 60 वर्ष की पुरी करने के आधार पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और श्रेणी 3 के मामले में 58 वर्ष की आयु पुरी करने पर 15 जनवरी, 2004 को आयोजित समिति की बैठक के संकल्प का उद्धरण पेपर बुक के अनुलग्नक पी 2 में रखा गया है जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है:

"....

कार्य सूचि संख्या 2

समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के बारे में।	समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के बारे में 18.11.03 को आयोजित समिति की बैठक में दिए गए निर्णय के आलोक में प्राप्त कानूनी सलाह के विश्लेषण के बाद, माननीय सदस्य डॉ. जितेंद्र सिंह, कुलाधिपति पटना विश्वविद्यालय, पटना ने सूचित किया कि उच्च शिक्षा विभाग, पटना के सचिव के पत्र संख्या 1961 दिनांक 12.11.1995 के अंतर्गत समिति में भी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। उपर्युक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार, सर्वसम्मति से यह फ़ैसला लिया गया था कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 18 वर्ष से कम आयु में की गई है, उनकी नियुक्ति की तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष है, उन्हें श्रेणी 4 के मामले में 60 वर्ष

	की आयु पुरी होने पर और श्रेणी 3 के मामले में 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा।

7. इसके दिनांक 15 जनवरी, 2004 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को 26 मार्च, 2012 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उन्होने अर्हक सेवा के 42 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो कि एक कर्मचारी सेवा प्रदान कर सकता है और तदनुसार वह 42 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने के बाद 31 मई, 2012 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया।

8. अपीलकर्ता का दावा था कि उसे समिति में दर्ज उसकी उम्र के साथ-साथ उसकी सेवा पुस्तिका में, अर्थात् १९ नवंबर, १९५४, में अभिलिखित आयु के आधार पर ६० वर्ष पूर्ण करने पर सेवा से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए ।विवाद ओर बिहार के उच्च न्यायालयय की खंड पीठ की राय के विरोध को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रगजवा नारायण मिश्रा और अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग समिति और अन्य[4] के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा 5 जनवरी, 2005 को दिए गए निर्णय द्वारा हल किया गया था । जिसे हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा देखा गया था और खंड पीठ द्वारा अपने आक्षेपित फैसले में पुष्टि की गई थी, जबकि अपीलकर्ता के सेवा में बने रहने के दावे को अस्वीकार करते हुए जब तक कि वह समिति में दर्ज अपनी आयु के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकिल प्रस्तुत करते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति नहीं दी जा सकती है केवल इसलिए कि वह अर्हक सेवा के 42 वर्ष पूरे कर लेता है, किसी विपरीत नियम की अनुपस्थिति में। उपर्युक्त फ़ैसला बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के अनुरूप था जो सेवानिवृत्ति के लिए केवल आयु को मानदंड के रूप में निर्धारित करता है।सेवानिवृत्ति के लिए एक मानदंड के रूप में सेवा की अवधि को निर्धारित करने वाला कोई नियम

4 2006 (1) पीएलजेआर 410

नहीं है और इस पर पूर्ण पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के विवाद को खारिज करने के निर्णय में भरोसा किया है.

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, रद्द निर्णय में हाईकोर्ट की खण्ड पीठ द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि हाईकोर्ट की दो खण्ड पीठों के बीच मतभेद था और जिसे रगजवा नारायण मिश्रा और अन्य मामले में (उपरोक्त) पूर्ण न्यायपीठ द्वारा हल कर लिया गया है. और इसका हाईकोर्ट द्वारा लगातार पालन किया गया और आगे प्रस्तुत करता है कि बहुमत अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश की पेशकश नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष/60 वर्ष होगी, जैसा भी मामला हो। तार्किक रूप से कोई भी व्यक्ति 40/42 वर्ष में सेवा के बाद किसी भी मामलों में इसे पार करना नहीं हो सकता है और समिति द्वारा 15 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में इसका समाधान किया और यह कभी भी अपीलकर्ता का विषय नहीं था जब उसे 26 मार्च, 2012 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि वह सेवा के 42 वर्ष पूरे करने पर 31 मई, 2012 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करेगा।

11. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि बिहार पेंशन नियम, १९५० के नियम ५७ और पेंशन नियम में खंड ४ के नियम ५ के साथ पठित बिहार सेवा कोड, १९५२, का नियम ७३ यह साफ़ करता है कि व्यक्ति के १८ वर्ष में आयु प्राप्त करने से पहले, जब अपीलकर्ता की नियुक्ति वर्ष १९७० में में गई थी, कोई भी सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यदि प्रवेश स्तर और निकास स्तर नियम बनाने वाले अधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति ४०/४२ वर्ष से अधिक सेवा में आगे नहीं जा सकता है.वर्तमान परिस्थितियों में जब अपीलकर्ता ने निर्विवाद रूप से मई २०१२ में ४२ साल में सेवा पूरी कर ली थी, तो उसे अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के प्रतिवादी के फ़ैसला को गलत नहीं कहा जा सकता है और इस स्तर पर इस पर और अधिक पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है जब यह

लगातार लगभग डेढ़ दशक से अधिक समय तक हाईकोर्ट द्वारा अनुसरण किया गया और इसमें किसी दखल अंदाजी की आवश्यकता नहीं है।

12. उपर्युक्त सांविधिक नियमों के प्रावधानों में, जिन्हें ऊपर संदर्भित किया गया है है, यह परिकल्पना की गई है कि सरकार, बिहार पेंशन नियमावली में नियम 5 डाला, जो अपीलकर्ता द्वारा समिति की सेवा में प्रवेश करने से बहुत पहले दिनांक 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी हुआ। एक संशोधन के आधार पर, पेंशन लाभों पर कीमत के एवज में लिए एक सरकारी कर्मचारी की अर्हक आयु 18 वर्ष हो गई, जो दिनांक 15 जनवरी, 1998 के आदेश द्वारा अपने सभी अधिनिस्त कर्मचारियों को साफ़ किया गया है कि 18 वर्ष सेवा में प्रवेश करने वाले सरकारी कर्मचारी की आयु होगी।

13. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कर्मचारियों में सेवा शर्तें सामान्यता सांविधिक नियमों द्वारा या उनके अभाव में बाह्यकारी बल वाले विनियमों या प्रशासनिक निर्णयों के अंतर्गत शासित होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेले वयस्क हो जाता है, वह सेवा में वैध अनुबंध करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 में यह परिभाषित किया गया है कि कौन अनुबंध करने के लिए सक्षम है। कानून के अनुसार, जिसके अधीन वह है, और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है और किसी भी कानून द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य नहीं है, जिसके अधीन वह है।

14. यह उपबंध स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि सेवा में वैध अनुबंध करने के लिए व्यक्ति को वयस्कता अधिनियम, 1875 के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त करनी होगी और वयस्कता की उम्र क्या हो सकती है इसे व्यस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के तहद परिभाषि किया गया है जो इस प्रकार हैः-

> "3. भारत में अधिवासित अधिकांश व्यक्तियों की आयु
>
> (1) भारत में अधिवासित प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष में आयु पूरी करने पर वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेगा न कि उससे पहले।

(2) किसी व्यक्ति की आयु की गणना करने में उसके जन्म की तारीख को एक पूरे दिन के रुप में शामिल किया जाना है । और उस दिन की अठारहवीं वर्षगांठ के आरंभ में उसे वयस्कता प्राप्त हुई समझी जाएगी।"

15. निर्विवाद रुप से वर्तमान मामले में अपीलकर्ता मई, 1970 में सेवा में प्रवेश में तारीख पर अवयस्क था और जब तक इसके विपरीत कोई विशिष्ट नियम न हो, अवयस्क सार्वजनिक रोज़गार प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य नहीं है.यह सच है कि प्रवेश स्तर पर न्यूनतम आयु हमेशा नियम बनाने वाले प्राधिकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।वर्तमान मामले में राज्य प्राधिकरण ने अपने पेंशन नियम, 1950 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा निर्धारित की है, जिसे एक संशोधन के द्वारा बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जो 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी है।यदि बिहार सेवा कोड, 1952 के अंतर्गत उपयुक्त समय पर न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी, तो कम से कम सरकारी पेंशन नियम, 1950 की सहायता लेना न्याय हित है ताकि यह माना जा सके कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रवेश बिंदु पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।इसके अलावा, यदि प्रवेश स्तर पर आयु को खुला छोड़ दिया जाता है, तो किसी भी उम्र का अवयस्क सार्वजनिक रोज़गार के लिए अपनी पात्रता की तलाश कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से अतार्किक है और नियम बनाने वाले अधिकारी का इरादा कभी नहीं हो सकता है।

16. बेशक, वर्तमान मामले में जब अपीलकर्ता ने सेवा में प्रवेश किया था, तब वह 15 वर्ष और 6 महीने का था और उसके व्यस्कता की आयु प्राप्त नहीं की थी और पेंशन नियम, 1950 के संदर्भ में प्रवेश बिंदु पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी जो प्राप्त नहीं की थी और एक तार्किक परिणाम के रूप में निकास बिंदु के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 60 वर्ष है, सेवा में कुल अवधि जो कोई सरकारी सेवा में प्रदान कर सकता है, वह 42 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और जब कोई असंदिग्ध स्व-स्पष्ट प्रावधान है, तो किसी भी परिपत्र या संकल्प या आदेश का कोई कानुनी और नियमों

की योजना में निहित अधिकार को समाप्त करने के लिए कोई वैद्य प्रभाव नहीं होगा। और यह पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा माना गया है, जिस पर हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के दावों को निरस्त करते हुए रगजवा नाराण मिश्र व अन्य (पूर्वोक्त) मामले पर भरोसा किया जो इस प्रकार हैः-

> "16. चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने जब प्रतिवादी समिति के साथ अनुबंध किया था तो वे व्यस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसके कानूनी प्रभाव और प्रभाव के अलावा, सेवा संबंध के संदर्भ में, एक अनुबंध की स्थिति पर प्रभाव और अंतिम परिणाम के बारे में कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने वैध सेवा में प्रवेश किया है, केवल तभी जब वह व्यस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है।इसलिए सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।निकास बिंदु के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है।दूसरे शब्दों में पेंशन लाभ के लिए किसी भी मामला में सरकारी सेवा की कुल अवधि 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस संदर्भ में, ऊपर उल्लिखित सरकारी परिपत्र पर विचार करने की आवश्यकता है। जब कोई स्पष्ट नियम प्रावधान है जो इसके विपरीत या असंगत है तो कोई परिपत्र या संकल्प या आदेश का प्रभावशाली नहीं होगा, किसी भी प्रावधान में निहित अधिकार को कम करने के लिए।यहां तक कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए 1998 के कथित परिपत्र को उनके लिए फायदेमंद माना जाता है, तो भी, इसे इस बिंदु पर बिहार पेंशन नियमों के मौजूदा वैधानिक प्रावधान साथ ही, बिहार सेवा संहिता के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है.इसलिए उस दृष्टिकोण से भी, याचिकाकर्ताओं को यह प्रतिवाद करने में अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्हें 58 वर्ष की आयु के बाद भी पद पर बने रहने का अधिकार है, हालांकि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में

इसका प्रावधान है, जो 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है.

17. तीसरा, यह कानून और न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का स्थापित प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति जो किसी एक या अन्य कारण से अनुचित लाभ उठाता है। सेवा में प्रवेश बिंदु को यह आग्रह करने में अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वहे उच्च लाभ दिया जाए और यदि यह आग्रह किया जाता है, तो स्पष्ट रुप से यह दर्शाता है कि सेवा में प्रवेश बिंदु पर कुछ गलत या अनियमित किया गया है।इस प्रकार, स्थापित सिद्धांत भी इस अदालत से राहत प्राप्त करने में एक बहुत मजबूत बाधा पैदा करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधान के आह्वान करके असाधारण, विशेषाधिकार, न्यायसंगत और विवेकाधीन रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर रहा है।

18. इसलिए, हमारी राय में दोनों रिट याचिकाओं में विवादित आदेश स्पष्ट रूप से, किसी भी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है।इसलिए कानून के प्रस्ताव को इस बात का स्पष्ट प्रमाण माना जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति में आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और एक व्यक्ति को सेवा में 40 वर्ष में आयु पूरी करने के बाद भी जारी नहीं रखा जा सकता है।इसलिए, यह साफ़ है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने 40 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है या 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसे मौजूदा नियम प्रावधान के अनुसार सेवानिवृत्त किया जाना है।इसलिए हमारा उत्तर बहुत साफ़ है और हम इस संदर्भ के अनुसार उत्तर देते हैं। इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट पूर्वोक्त विनिश्चयों में विरोधाभासी दृष्टिकोण एक अच्छा कानून नहीं होगा।"

17. एक मत पटना हाईकोर्ट की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसका संदर्भ दिया गया है, दूसरा मत जो झारखंड हाईकोर्ट द्वारा संदर्भित किया गया है है, जिसका संदर्भ अपीलकर्ता द्वारा अपील में दिया गया है, लेकिन जो बात मुझे आगे अधिक आश्वस्त करती है वह यह है कि पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की 5 दिसंबर, 2005 के निर्णय जो कम से कम बिहार राज्य में लगभग डेढ़ दशक तक लगातार अनुसरण किया गया है और आगे एकल न्यायाधीश/खंड न्यायपीठ ने पटना हाईकोर्ट की पूर्ण न्यायपीठ पर भरोसा करते हुए अनेक आदेश पारित किए है।जो विचार व्यक्त किया गया है वह एक विश्वसनीय विचार है और मेरे विचार में, केवल इस कारण से पलटना उचित नहीं होगा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण वैधानिक नियमों की योजना की सराहना करने में अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है, जिसका हवाला दिया गया है।

18. निःसंदेह, अपीलकर्ता को यह प्रतिवाद करने में अनुमति नहीं दी जा सकती है कि बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 को ध्यान में रखते हुए समिति के अभिलेख में दर्ज उनकी जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने का अधिकार है ।नियमों की योजना से यह साफ़ है कि बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित है । जो सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगा और व्यक्ति को पेंशन नियम, 1950 को ध्यान में रखते हुए सेवा में 42 वर्ष में आयु पूरी करने के बाद जारी नहीं रखा जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकारी कर्मचारी जिसने 60 वर्ष में आयु प्राप्त करने पर 42 वर्ष की नौकर पूरी कर ली थी, दोनों निहित नियमों की योजना के संदर्भ में सेवानिवृत्त किया जाना है, इस पर पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पर भरोसा किया गया है ।

19. नागलैंड वरिष्ट सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन और अन्य बनाम नगालैंड राज्य और अन्य 2010 (7) एस. सी. सी. 643 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि संगठन और

अन्य बनाम नगालैंड राज्य और अन्य, 2010 (7) एस. सी. सी. 643 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि कर्मचारी कल्याण संगठन और अन्य बनाम नगालैंड राज्य और अन्य, 2010 (7) एस. सी. सी. 643 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि कर्मचारी कल्याण संगठन और अन्य बनाम नगालैंड राज्य और अन्य, 2010 (7) एस. सी. सी. 643 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि कर्मचारी कल्याण संगठन और अन्य बनाम नगालैंड राज्य और अन्य 2010 (7) एस. सी. सी. 643 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि कर्मचारी कल्याण संगठन और अन्य कर्मचारी कल्याण संगठन और अन्य राज्य और अन्य बनाम नगालैंड राज्य। सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, 1991 की धारा 3 की वैद्यता की जाँच करने का अवसर था, जैसा की सार्वजनिक रोजगार (संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

> “3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या आदेशों में निहित किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक रोजगार में कोई व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार में शामिल होने में तारीख से 35 वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह 60 वर्ष में आयु प्राप्त नवहं कर लेता है, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
>
> (2) सार्वजनिक रोजगार के अधीन कोई व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन सेवानिवृत होगा जिस दिन वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या जिसके अंतर्गत वह सार्वजनिक रोजगार के 35 वर्ष पूरे करता है, जो भी पहले हो।"

इस अदालत ने आगे कहा कि सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए एक वैकल्पिक मानदंड के रूप में सेवा की अधिकतम अवधि का निर्धारण, कल्पना के किसी भी सीमा तक, रोज़गार योजना के किसी भी मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।पैरा 40 यहां उद्धृत किया गया हैः-

> “40. हम डरे हुए हैं, के. नागराज मामला [(1985) 1 एससीसी 523 अपीलकर्ताओं की मदद करने के बजाय राज्य के रुख का समर्थन करता है।सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए एक विकल्प मानदंड के रूप में अधिकतम सेवा अवधि का निर्धारण, किसी भी तरह से, रोज़गार योजना के किसी भी मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है।अनेक बाध्यकारी कारण हो सकते हैं जिनके कारण सरकार (या विधायिका) को निर्दिष्ट वर्ष पूरे होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति का नियम निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है।यदि कारण प्राप्त करने की मांग की गई, वस्तु के लिए प्रासंगिक है तो ऐसे प्रावधान को शायद ही गलत ठहराया जा सकता है।"

20. वर्तमान मामले में नियमों की योजना के अलावा, जिसके बारे में एक संदर्भ दिया गया है, अपीलकर्ता वयस्कता प्राप्त करने की आयु से पहले सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता है, यदि बिहार सेवा कोड के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर न्यूनतम आयु का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, प्रार्थना के रूप में में गई है, अलगाव में स्वीकार किया जाता है और प्रवेश स्तर पर आयु खुली छोड़ दी जाती है, तो यह हमें एक ऐसे चरण में ले जाएगा जहां एक बच्चा या किसी भी उम्र का अवयस्क सार्वजनिक रोज़गार में प्रवेश करने के लिए अपनी पात्रता का दावा कर सकता है जो कि स्पष्ट रुप से अतार्किक और कानून में अस्वीकार्य है।

21. इस प्रकार, नियमों की मौजूदा योजना के अंतर्गत अर्हक सेवा जो किसी भी तरीके से प्रदान की जा सकती है वह 42 वर्ष से अधिक नहीं होगी और सरकार द्वारा 15 जनवरी, 1998 के अपने परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है और इसे समिति द्वारा 15 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में, ध्यान में रखा गया था जो चुनौती की विषय वस्तु नहीं थी और अपीलकर्ता को 31 मई, 2012 को 42 वर्षों का

पूर्ण रोज़गार प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की सूचना दी गई थी, जिसे मेरी राय में नियमों की योजना का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

22. अपील सारहीन है और तदनुसार ख़ारिज की जाती है।

23. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, का निष्पादन किया जाता है।

(अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

28 मई, 2020

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।